



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Ref

सं. 531]

मई विल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1995/पौष 5, 1917

No. 531] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1995/PAUSA 5, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1995

सं. 39/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.फा.नि. 810 (श्र).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्घरण (जिसके अन्तर्गत उसका उद्घरण न किया जाना भी है) के बारे में साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट और किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित और “आयात और निर्यात नीति 1 अप्रैल, 1990—मार्च, 1993 के पैरा 333 के उप-पैरा (2), पैरा 334 तथा पैरा 345 के उप-पैरा (3) और उप-पैरा (4) या आयात निर्यात नीति 1 अप्रैल, 1992—31 मार्च, 1997 के पैरा 102” के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार भारत में विक्रय के लिए अनुज्ञात सभी उत्पाद

शुल्क या माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) प्रभार्य उत्पाद शुल्क, जो उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घरणीय उत्पाद शुल्क से, जितना प्रत्येक के उस सीमाशुल्क की, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारत के बाहर उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर इस प्रकार उद्घरणीय होगा मानो उसका भारत में आयात किया गया हो, 50 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट प्राप्त है, 1 अप्रैल, 1992 को प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्घरीत नहीं किया जा रहा था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त माल पर उद्घरणीय उत्पाद शुल्क जो यदि उक्त प्रथा न होती तो शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम

द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र निकासियों पर प्रथम वर्गित अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेश प्रत्येक सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक है, ऐसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र निकासियों की बाबत, जिन पर उक्त प्रथा के अनुसार उपर्युक्त अधिकार के दौरान उन्पाद उक्त शुल्क उदाहरण नहीं किया गया था, संदर्भ किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

[फा.सं. 268/46/93-सी.एक्स-8]

मलिका आर्या, अवर सचिव

टिप्पण : यह अधिसूचना केन्द्रीय उन्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अधीन इसलिए जारी की गई है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत समय पर प्रचालित साधारण प्रथा के अनुसार शास्त्र प्रतिशत नियांतोन्मुख उपकरणों की घरेलू टैरिफ क्षेत्र निकासियों की बाबत प्रत्येक सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक उत्पाद शुल्क 1-4-1992 से 28-2-1993 की अवधि के दौरान संदर्भ किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1995

NO. 39/95—CENTRAL EXCISES (NON-TARIFF)

G.S.R. 810 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise chargeable on all excisable goods (hereinafter referred to as the said goods) specified in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1985) and produced or manufactured in a hundred per cent export oriented undertaking or a free trade zone and allowed to be sold in India under and in accordance with the provisions of "sub-paragraph (2) of paragraph 333, paragraph 334 and

sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 345 of the Import and Export Policy, April, 1990-March, 1993 or paragraph 102 of the Export and Import Policy, 1 April, 1992—31 March, 1997" exempted from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excises and Salt Act, 1944 as is in excess of the amount calculated at the rate of 50% of each of the duties of customs, which would be leviable under section 12 of the Customs Act, 1952 (52 of 1952) read with any other notification for the time being in force issued under sub-section (1) of section 25 of the said Customs Act on the like goods produced or manufactured outside India as if imported into India were not being levied under section 3 of the first-mentioned Act, during the period commencing on the 1st day of April, 1992 and ending with the 28th day of February, 1993.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of Central Excise & Salt Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government hereby directs that duty of excise leviable on the said goods in excess of 50% of each of duties of Customs payable under section 3 of the first-mentioned Act, on Domestic Tariff Area clearances by hundred per cent export oriented undertaking but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such Domestic Tariff Area clearances on which the said duty of excise were not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 268/46/93-CX-8]
MALLIKĀ ARYA, Under Secy.

Note :—This Notification has been issued under section 11C of Central Excises and Salt Act, 1944, so as to provide that in accordance with a general practice that was prevalent at the relevant time, the duty of excise in excess of 50% each of duties of customs in respect of DTA clearances of 100% export oriented Undertaking shall not be required to be paid during the period from 1-4-1992 to 28-2-1993.